

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-305 xi /17/51(01)/2017
देहरादून, दिनांक, 21 जुलाई, 2017

कार्यालय-आदेश

श्री प्रकाश सिंह रावत पूर्व में जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी के पद पर तैनात थे। उन्हें प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी का प्रभार भी दिया गया था। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2012 में जनपद-रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में बरती गयी कथित लापरवाही/त्रुटियों हेतु श्री प्रकाश रावत के अतिरिक्त अन्य उत्तरदायी अधिकारियों को भी आरोपित करते हुए औपचारिक अनुशासनिक जांच करायी गयी। पूर्व में नामित जांच अधिकारी क्योंकि वर्ष-2014 में सेवानिवृत्त हो गये, फलतः उनके स्तर पर समय कम होने के कारण जांच पूरी नहीं की जा सकी। क्योंकि प्रकरण पंचायतराज विभाग से सम्बन्धित था। अतः इसकी जांच तथा जांच अधिकारी का नामांकन भी पंचायतराज विभाग के स्तर से भी किया गया। पंचायतराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-219/XII(1)/2017-92(02)2013T.C-VII दिनांक 6.3.2017 के द्वारा श्री हरि चन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2. प्रश्नगत प्रकरण में लगाये गये आरोप, आरोपी अधिकारी के द्वारा दिये गये उत्तर का सारांश एवं जांच अधिकारी के द्वारा दिनांक 26.4.2017 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गयी जांच आख्या का निष्कर्ष निम्नवत है:-

आरोप-(1) "(जो प्रभारी सचिव, पंचायतीराज के पत्र दिनांक 15.5.2017 के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग को निर्णय लेने हेतु प्राप्त हुयी) कार्यालयाध्यक्ष होने के बावजूद आपका यह उत्तरदायित्व है कि अपने जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन अपने स्तर से अधीनस्थ कर्मचारियों से सम्पदित करायें। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2012 में आपके स्तर से सभी अभ्यर्थियों के बायोडाटा संवर्गवार, प्रवेश पत्र भेजने से पूर्व अद्यतन करने चाहिए थे। इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से पूर्व में ही निर्देश दिये जा चुके थे। फिर भी आपके स्तर से अभ्यर्थियों के बायोडाटा तैयार करने में नितान्त लापरवाही व असावधानी बरती गई जिसके कारण त्रुटियां हुई हैं। आपके द्वारा अपने पत्र संख्या-1141/दिनांक 26.2.2013 में स्वयं त्रुटियों को स्वीकार भी किया है। अतः राजकीय कार्यों में लापरवाही करने, समय से निष्पादित न करने एवं अधीनस्थ कर्मिकों पर पर्याप्त नियंत्रण न रख पाने के लिए आप दोषी पाये गये हैं।

आरोप-(2) आप दिनांक 31.7.2012 से जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर जनपद में कार्यरत हैं। आपका कार्य/उत्तरदायित्व अपने पद के अनुरूप पूर्णरूप से निर्वहन करना था। विभाग में गतिमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2012 में घोषित परीक्षा

परिणाम के सापेक्ष जनपद उत्तरकाशी से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों से प्राप्त आपत्तियों के क्रम में जांच /परीक्षणोपरान्त अभ्यर्थियों की अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणी एवं क्षेत्रीय आरक्षण (उपश्रेणी) आदि में लगभग 07 त्रुटियों प्रकाश में आयी हैं। इस दृष्टिगत जनपद का परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है। इस प्रकार आपने सरकारी कर्मचारी /अधिकारी आचरण नियमावली 1956 (यथा संशोधित नियमावली 2010) में दी गयी विद्यमान व्यवस्था के आधार पर अनुशासन हीनता /कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा आदि के दोषी हैं। ”

आरोपी अधिकारी के द्वारा दिया गया उत्तर – आरोप के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशों के परिपालन में कार्यालय पत्रांक –1141/23-पं0/स्था0/2012-13, दिनांक 26.2.2013 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जनपद एवं निदेशालय स्तर से प्राप्त आपत्तियों एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार घोषित परीक्षा परिणामों में पायी गयी विसंगतियों की जांच परीक्षार्थियों के मूल आवेदन –पत्रों से करके आख्या निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड , देहरादून को प्रेषित की गयी थी। आरोप पत्र में इंगित किया गया है कि मेरे द्वारा पत्रांक –1141, दिनांक 26.2.2013 के द्वारा स्वयं त्रुटियों को स्वीकार किया गया है जो कि सरासर गलत आरोप है। क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा त्रुटियां स्वीकार नहीं की गयी थी वरन त्रुटियों को संशोधित किया गया था। इसलिए आरोप मान्य नहीं है। प्रेषित आख्या के अनुसार 14 आपत्तियां/विसंगति थी, जिनमें क्रमांक 01 एवं 02 विसंगति पन्तनगर विश्वविद्यालय से तथा क्रमांक 4,5,7 व 14 लिपिकीय त्रुटि मेरे पूर्व अधिकारी के स्तर से प्रेषित बायोडाटा में हुयी थी, क्योंकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती विज्ञप्ति संख्या-380/पं0रा0वि0/2012-13, दिनांक 20.6.2012 के अनुसार आवेदन- पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 16 जुलाई 2012 थी। आवेदन पत्रों के अनुसार बायोडाटा मेरे पदभार ग्रहण करने से पूर्व कम्प्यूटर में फीड कर दिया गया था। जबकि मेरे द्वारा दिनांक 1.8.2012 को जिला पंचायत राज अधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्रमांक 4,5,7 व 14 पर अंकित लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित कर पन्तनगर विश्वविद्यालय को पूर्व में ही ई-मेल द्वारा भेजा गया था। शेष 8 बिन्दु जो कि आपत्तिकर्ताओं द्वारा जनपद/निदेशालय स्तर पर प्रस्तुत किये गये थे, तर्क संगत न होने के कारण तत्समय ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निराधार/निरस्त करने की संस्तुति की गयी थी। इस प्रकार समस्याओं का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व ही निस्तारण कर लिया गया था। आरोप- पत्र के अनुसार निराधार/तर्कहीन 8 आपत्तियों के लिए भी अधोहस्ताक्षरी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है।

अतः स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराना है कि पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा परिणाम का निदेशक महोदय , पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जांच करवाकर संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करवाया गया। यह भी संज्ञान में लाना है कि अधोहस्ताक्षरी इस जनपद में जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और अपने विभाग के साथ-साथ पंचायतराज विभाग के समस्त कामिकों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्वहन किया गया है। पंचायतराज विभाग के अनतर्गत दिनांक 1.8.2012 के द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भर्ती जैसे वृहद कार्यक्रम, त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन कार्यक्रम एवं

पिछड़ी जाति के रैपिड सर्वे जैसे समयबद्ध कार्यक्रमों का सफल सम्पादन किया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही, असावधानी एवं त्रुटियां नहीं की गयी हैं।

जांच अधिकारी की जांच आख्या— प्रश्नगत प्रकरण में आरोपी अधिकारी पर लगाये गये आरोपों, उक्त आरोपों के सम्बन्ध में आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गये जवाब तथा इस सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों के अनुशीलन / परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उत्तराखण्ड में अधिकांश समूह 'ग' के पदों पर चयन की कार्यवाही किसी न किसी चिन्हित संस्था के माध्यम से करायी जाती है। जबकि तत्समय पंचायतीराज विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन— पत्रों को जमा कराने एवं आवेदन—पत्रों की जांच आदि का सम्पूर्ण कार्य/दायित्व जिला पंचायतराज अधिकारी को सौंपा गया था तथा परीक्षा कराने एवं परिणाम तैयार करने का एकमात्र कार्य पन्तनगर विश्वविद्यालय को दिया गया था। जिला पंचायतराज अधिकारी एवं उनके कार्यालय द्वारा उक्त कार्य प्रथम बार सम्पन्न कराया गया था, जिसके फलस्वरूप उनके पास अनुभव का अभाव रहा इस कारण से आवेदन पत्रों एवं उनके साथ संलग्न अभिलेखों आदि का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी एवं क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर सूचना तैयार कर पन्तनगर विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने में त्रुटियां हुई थी, जिसको निदेशालय स्तर पर ठीक कराकर पुनः संशोधित सूचना पन्तनगर विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी गयी तथा पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित सूचना के आधार पर संशोधित / अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तथा इस परीक्षा परिणाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी एवं इस अन्तिम परीक्षा परिणाम के आधार पर तत्समय चयन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अपने-अपने जनपद में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। इस प्रकार आरोप में जो त्रुटियां किए जाने का आरोप लगाया गया है, उन त्रुटियों को आरोपी अधिकारी द्वारा तत्समय सुधार कर लिया गया था तथा इस त्रुटियों से अंतिम परीक्षा परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

जांच अधिकारी की जांच आख्या, विषयगत मामले में अपचारी अधिकारी पर लगाये गये आरोप, उनके द्वारा दिये गये उत्तर, जांच अधिकारी के द्वारा इस सम्बन्ध में जो आख्या/निष्कर्ष निकाला गया, उसका सार यह है कि अभ्यर्थियों से सम्बन्धित आवेदन—पत्रों एवं उनके साथ संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी एवं क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर सूचना तैयार कर पन्तनगर विश्वविद्यालय को सूचना प्रेषित करने में त्रुटि हुई थी, जिसको निदेशालय स्तर पर ठीक कराकर पुनः संशोधित सूचना पन्तनगर विश्वविद्यालय को प्रेषित की गयी और संशोधित सूचना के आधार पर संशोधित/अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा परिणाम में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लगाये गये आरोपों के अनुसार त्रुटियां होना तो पाया गया है, परन्तु आरोपी अधिकारी द्वारा इन त्रुटियों का तत्समय सुधार कर लिया गया था तथा इन त्रुटियों से अन्तिम परीक्षा परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जांच अधिकारी ने आरोपी अधिकारी के सम्बन्ध में

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद अनुभव का अभाव होने का भी निष्कर्ष निकाला है। अतः सार्वजनिक रोजगार जैसे संवेदनशील प्रकरणों के परीक्षा परिणामों में अनुभव की कमी एवं अपेक्षित सर्तकता के अभाव के कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित न रहते हुए भी जहां त्रुटियां रह जाना प्रमाणित हो जाय, तो आरोपी अधिकारी को पूर्णतः दोषमुक्त नहीं माना जा सकता। अतः उल्लिखित स्थिति में आरोपित अधिकारी श्री प्रकाश रावत, जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी (तत्कालीन प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी) को इस आधार पर व्यक्तिगत पत्रावली के माध्यम से चेतावनी देते हुए लम्बित जांच को एतद्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।


(मनीषा पेंडार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-305(1)xi/17/51(01)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 ग्राम विकास मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश सहित कि वे आदेश की तामीली सम्बन्धित अधिकारी को सुनिश्चित कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(तुलसी राम)
अपर सचिव।